

धनपरीक्षा - १५/०१/१९८८ ई. नं. २३/८८

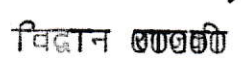
दिनांक

आज्ञा पत्र

२०-३-१८

पत्रावली वास्ते आदेश प्रस्तुत ।

बहस पर मन्त किया गया । वकील अपीलान्ट ने जाहिर किया कि विवादित आराजी ख० नं० ६ ७, ९, १०, ११, ५, ८, ११९ से १२२; १२४ से १२७ कुल कित्ता-१५ रकबा १५.५९ हैक्टर ग्राम गोरधनपुरा जिसके पुराने ख० नं० २, २/४२१, ७३ व ७४ रकबा ६२ बीघा १३ बिस्वा थे । इस आराजी में १/४ हिस्से की भूमि बैंक में रहन किये जाने पर बैंक ने इस भूमि की सार्वजनिक बोली लगाई जिसमें अधिकतम बोली अपीलान्ट द्वारा लगाई जाकर डुडाई गई । जिसमें १७०००/- रुपये जमा कर उक्त आराजी काब्जा ले लिया किन्तु राजस्व रेकार्ड में अप्रार्थी/रेस्पोंडेंट का नाम रह जाने से वह इस आराजी को पुनः रहन रखकर प्रार्थी/अपीलान्ट को बेदखल करने पर आमादा है जिसका इसे कोई अधिकार नहीं है। अतः प्रार्थना पत्र स्थगन स्वीकार किया जावे। अदालत मातहत ने मेरा प्रार्थना पत्र विरुद्ध खारिज किया है । अपील स्वीकार की जाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

विद्वान  वकील अपीलान्ट की बहस का

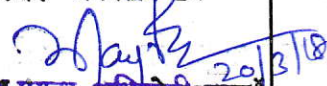


भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

जाति अन्वय पिछडा वर्ग का सदस्य है तथा रेस्पोजेन्ट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है जिसकी भूमि किसी भी स्थिति में अपीलान्ट को नहीं दी जा सकती। इस भूमि पर अपीलान्ट का कोई कब्जा नहीं है। अदालत मातहत का निर्णय उचित एवं विधिक है। अपील खारित की जावे।

बहस बगौर समाप्त की गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। यह स्वीकृत तथ्य है कि अपीलान्ट स्वर्ण जाति अन्वय पिछडा वर्ग का सदस्य है तथा रेस्पोजेन्ट अनुसूचित जन जाति का सदस्य है। अनुसूचित जन जाति के सदस्य की भूमि उच्च जाति के सदस्य को नहीं दी जा सकती जैसा राज० कार्यकारी अधिनियम की धारा-42 ख में स्पष्ट किया गया है। राजस्व रेकार्ड में सम्वत् 2061 से 2064 में रेस्पोजेन्ट सं०-1 विवादित आराजी का 1/4 हिस्से का रेकार्ड खातेदार कार्यकार है। अपीलान्ट का विवादित आराजी पर न तो कब्जा प्रमाणित है और न ही रेकार्ड में अपीलान्ट दर्ज है। अदालत मातहत ने अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र विवादित आराजी पर कब्जा कार्यकार प्रमाणित नहीं होने पर खारिज किया है। अदालत मातहत के इस निर्णय में किसी प्रकार की कानूनी भूल नहीं है। जिससे अदालत मातहत के निर्णय में कोई हस्तक्षेप उचित नहीं मानते हैं।

अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है तथा विद्वान सहायक कलेक्टर सीकर का निर्णय दिनांक 15-9-2007 को यथावत रखा जाता है। निर्णय सुनाया गया।


20/3/18
पू. मुख्यालय अपील अधिकारी
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
सीकर